RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 346
दि. 19.04.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महंगाई के दौर में राहत की सांस-केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी बना बड़ा सहारा

नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने लाखों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है। भारत सरकार के इस फैसले के तहत अब डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यह निर्णय न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी आर्थिक संबल लेकर आया है, जिससे उनकी मासिक आय में सीधा इजाफा होगा और महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर आई है जब रोजमर्रा की जरूरतों—खाद्य पदार्थ, ईंधन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं—की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में डीए में वृद्धि कर्मचारियों के लिए केवल वेतन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि जीवन स्तर को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। सरकार के इस कदम से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर लगभग 1.19 करोड़ लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे, जो इसे हाल के समय का एक बड़ा वित्तीय निर्णय बनाता है।

महंगाई भत्ता मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 7वां वेतन आयोग के तहत यह वृद्धि तय की गई है, और इसी ढांचे में आने वाले सभी कर्मचारियों व पेंशनरों पर यह लागू होगी। इससे पहले

अक्टूबर 2025 में डीए को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था, और अब यह बढ़कर 60 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए नियमित अंतराल पर कदम उठा रही है।

इस फैसले की एक खास बात यह है कि इसे पिछली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी से लेकर अब तक का एरियर भी मिलेगा। यह एरियर एकमुश्त भुगतान के रूप में आएगा, जिससे लोगों को अतिरिक्त आर्थिक मजबूती मिलेगी। कई परिवार इस राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जरूरी खर्चों के लिए कर सकेंगे, जबकि कुछ इसे बचत या निवेश के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

डीए में यह बढ़ोतरी केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर भी असर डालती है। जब लाखों लोगों की आय बढ़ती है, तो बाजार में खपत बढ़ती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। खुदरा बाजार, सेवा क्षेत्र और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी होती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। इस तरह यह फैसला अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। हालांकि, इस राहत के बीच कर्मचारियों की नजर अब अगले बड़े बदलाव—8वें वेतन आयोग—पर टिकी हुई है। कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से वेतन संरचना में व्यापक सुधार की मांग उठाई है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने सरकार को सौंपे अपने ज्ञापन में 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 69,000 तक पहुंच सकता है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा।

इसके अलावा, संगठनों ने परिवार की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को शामिल करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने और विभिन्न भत्तों को तर्कसंगत बनाने की भी मांग की है। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन या उसके लागू होने की कोई आधिकारिक समयसीमा घोषित नहीं की गई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो इसका पूर्ण क्रियान्वयन 2028 तक संभव हो सकता है।

वर्तमान परिदृश्य में डीए की यह 2 प्रतिशत वृद्धि कर्मचारियों के लिए राहत की एक मजबूत कड़ी के रूप में सामने आई है। यह न केवल उनकी आय को बढ़ाती है, बल्कि उन्हें भविष्य के प्रति अधिक आत्मविश्वास भी देती है। बढ़ती महंगाई के दौर में जब आम आदमी अपने खर्चों को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे में सरकार का यह कदम निश्चित रूप से सकारात्मक और स्वागत योग्य माना जा रहा है।

आखिरकार, यह निर्णय केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की उम्मीदों और जरूरतों से जुड़ा है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की राहत का इंतजार करते हैं। आने वाले समय में यदि इसी तरह के और कदम उठाए जाते हैं, तो यह न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारेंगे, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को भी मजबूती प्रदान करेंगे।

महाराष्ट्र में 'जीरो टॉलरेंस' की कड़ी चेतावनी: फडणवीस ने अपराधियों के खिलाफ खोला मोर्चा, हाई-लेवल बैठक में हर केस की बारीकी से समीक्षा

मुंबई। महाराष्ट्र में बढ़ते संवेदनशील अपराधों और कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने अब पूरी सख्ती के साथ मोर्चा संभाल लिया है। देवेंद्र फडणवीस ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति को स्पष्ट रूप से लागू करने का संकेत देते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। यह बैठक केवल औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर बड़े और चर्चित मामले की गहराई से पड़ताल की गई और जांच एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में मुंबई के मंत्रालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख समेत वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि सरकार इन मामलों को लेकर कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि जांच केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका अंतिम लक्ष्य दोषियों को अदालत में सजा दिलाना होना चाहिए। इसके लिए हर केस में वैज्ञानिक साक्ष्य, मजबूत दस्तावेजीकरण और समयबद्ध रिपोर्टिंग को अनिवार्य बताया गया।

बैठक में सबसे पहले नासिक के चर्चित मामले पर चर्चा हुई, जिसमें स्वयंभू बाबा अशोक खरात का नाम सामने आया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पुलिस केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे केस को इस तरह तैयार करे कि अदालत में दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पीड़ितों की सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई, ताकि वे बिना किसी भय के न्याय प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। यह भी निर्देश दिया गया कि अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर पीड़ितों से संवाद बनाए रखें, जिससे उनका विश्वास बना रहे।

इसके बाद नासिक में सामने आए कथित धर्मांतरण मामले पर चर्चा हुई, जिसे देवेंद्र फडणवीस ने अत्यंत गंभीर बताया। इस मामले में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़े पहलुओं का जिक्र करते हुए उन्होंने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जांच यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि इस मामले के पीछे यदि कोई संगठित नेटवर्क या पैटर्न काम कर रहा है, तो उसे पूरी तरह उजागर किया जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक दबाव, प्रलोभन या धोखे से जुड़े मामलों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ड्रग्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने गोरेगांव में सामने आए ड्रग्स केस की भी समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि नशे का कारोबार केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा गंभीर खतरा है। पुलिस को निर्देश दिए गए कि राज्यभर में ड्रग्स के सप्लायर्स और पेडलर्स के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाए और इस नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल छोटे स्तर के अपराधियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे सप्लाई चेन को तोड़ना जरूरी है।

बैठक में अमरावती के परतवाड़ा क्षेत्र से जुड़े अयान अहमद मामले पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस मामले में मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पीड़ितों के मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेशेवर काउंसलर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद ली जाए, ताकि पीड़ित बिना किसी डर या दबाव के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने कहा कि कानून का डर अपराधियों में होना चाहिए, न कि पीड़ितों में।

इस पूरी बैठक से यह साफ संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र सरकार अब अपराध के खिलाफ एक समग्र और सख्त रणनीति अपनाने जा रही है, जिसमें केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि न्याय, संवेदनशीलता और सिस्टम की मजबूती तीनों को बराबर महत्व दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सभी मामलों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाए।

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर सवाल, कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा का तीखा हमला

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने शनिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लोकतंत्र और कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और जनता अब बदलाव चाहती है। भट्टाचार्य ने तीखे शब्दों में कहा कि राज्य सरकार "जीवित जीवाश्म" की तरह हो गई है, जो अब केवल उधार के समय पर चल रही है। उनके अनुसार, जनता का विश्वास सरकार से लगभग खत्म हो चुका है और लोगों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन प्रशासन ने इसे नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए।

भाजपा नेता ने दावा किया कि 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी के 253 पदाधिकारियों की हत्या कर दी गई, जो राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का बड़ा संकेत है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। उनके मुताबिक, "सिंडिकेट राज", बाहुबल और राजनीतिक दबाव के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई है।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2011 में ममता बनर्जी ने "लोकतंत्र की बहाली" के नारे के साथ 34 वर्षों से सत्ता में रही वाम मोर्चा सरकार को हटाया था। लेकिन भट्टाचार्य का आरोप है कि सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उसी प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को अपनाया, जिसमें हिंसा और दबाव की राजनीति प्रमुख रही। उनके अनुसार, पिछले दो कार्यकालों में राज्य में "आतंक का माहौल" बना रहा, जहां आम लोगों और विपक्ष को खुलकर अपनी बात रखने में डर लगता है।

भाजपा का कहना है कि लगातार चुनावों में मतदाताओं के भीतर असंतोष बढ़ता गया, लेकिन भय के कारण वे खुलकर सामने नहीं आ पाए। पार्टी का दावा है कि अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि राज्य की जनता लोकतंत्र की वास्तविक बहाली चाहती है और निष्पक्ष वातावरण में अपनी आवाज उठाना चाहती है। हालांकि, इन आरोपों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ओर से समय-समय पर पलटवार भी किया जाता रहा है, जिसमें भाजपा पर राज्य की छवि खराब करने और राजनीतिक लाभ के लिए माहौल को भड़काने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन चुनावी माहौल के बीच इस तरह के बयान और आरोप-प्रत्यारोप राज्य की राजनीति को और गर्माते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से तीखे टकराव और वैचारिक संघर्ष के लिए जानी जाती रही है। ऐसे में कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच आम मतदाता किसे सही मानता है और आने वाले समय में राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।

आस्था की आड़ में अपराध का साम्राज्य-नासिक सेंट्रल जेल में बंद होगा अशोक खरात, बढ़ती जा रही पीड़िताओं की संख्या

नासिक। आस्था और विश्वास का चोला ओढ़कर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले स्वघोषित धर्मगुरु अशोक खरात पर कानून का शिकंजा अब लगातार कसता जा रहा है। जिस व्यक्ति को कभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान समझते थे, वही अब गंभीर आपराधिक आरोपों के चलते सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। शनिवार को नासिक की अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 30 अप्रैल तक जेल में रखने का आदेश दिया, जिसके बाद अब उसका नया ठिकाना नासिक रोड सेंट्रल जेल तय हो गया है।

यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएन इचपुरानी की अदालत द्वारा सुनाया गया, जहां आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। मामले की गंभीरता और सुरक्षा कारणों को देखते हुए अदालत परिसर में पेशी कराने के बजाय यह कदम उठाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और जांच के दौरान उसे न्यायिक हिरासत में रखना आवश्यक है।

यह पूरी कार्रवाई यौन शोषण के चौथे मामले में की गई पेशी के बाद सामने आई है, लेकिन जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे आरोपों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब तक अशोक खरात के खिलाफ कुल 12 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 8 सीधे तौर पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का संकेत है कि मामला केवल एक-दो घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि

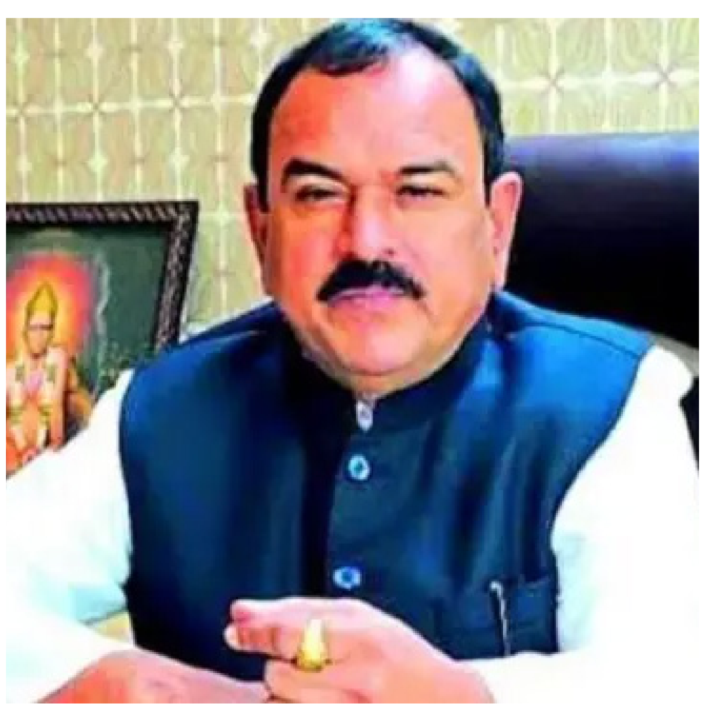

यह एक संगठित और लगातार चलने वाला अपराध प्रतीत होता है।

पीड़िताओं के बयान इस पूरे प्रकरण की भयावहता को और उजागर करते हैं। एक पीड़िता ने बताया कि वह अपने पारिवारिक विवादों और मानसिक तनाव से परेशान होकर खरात के पास गई थी, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन आरोप है कि खरात ने उसकी इसी मजबूरी और विश्वास का फायदा उठाते हुए उसके साथ शारीरिक शोषण किया। यह केवल एक मामला नहीं, बल्कि कई ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं, जहां आस्था के नाम पर लोगों के भरोसे को तोड़ा गया।

इस पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जो हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि अभी और भी पीड़िताएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि कई लोग सामाजिक दबाव और डर के कारण सामने आने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे और भी चौंकाने वाले खुलासे होते हैं।

पुलिस अब इस मामले को और गहराई से समझने के लिए आरोपी से लगातार पूछताछ करना चाहती है। इसी क्रम में रविवार को एक बार फिर अशोक खरात को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पांचवीं पीड़िता के आरोपों के आधार पर पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के प्रभाव, उसके संपर्कों और अपराध के पैटर्न को समझने के लिए हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है।

इस पूरे घटनाक्रम ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—आखिर किस तरह लोग बिना किसी ठोस प्रमाण या सत्यापन के किसी व्यक्ति को 'धर्मगुरु' मान लेते हैं और उस पर आंख मूंदकर भरोसा कर बैठते हैं। ऐसे मामलों में केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आस्था के नाम पर लोगों का शोषण न कर सके।

अशोक खरात का मामला यह भी दिखाता है कि कानून भले ही देर से कार्रवाई करे, लेकिन जब करता है तो सख्ती से करता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आते हैं या नहीं। फिलहाल, नासिक सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे बंद यह 'सफेदपोश बाबा' अपने कर्मों का हिसाब दे रहा है, और पीड़िताओं को उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का प्रतीक बन चुका है, जहां अंधविश्वास और आस्था का दुरुपयोग कर अपराधों को अंजाम दिया जाता है।

संपादकीय

गिरा संविधान संशोधन बिल

जैसे कि पहले से कायस लगाए जा रहे थे, शुक्रवार को लोकसभा में संविधान में प्रस्तावित 131वां संशोधन बिल मतदान के बाद गिर गया। दरअसल, यह बिल देश में महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। राजनीतिक पंडित पहले ही कह रहे थे कि संविधान संशोधन के लिये जरूरी दो तिहाई बहुमत सरकार के पास नहीं है, जिससे बिल के पारित होने पर संशय था। वैसा ही हुआ और राजग सरकार दो तिहाई वोट हासिल करने में विफल रही। बिल के समर्थन में 298 और इसके विरोध में 230 वोट पड़े। आखिरकार सरकार की ओर से कहा गया कि अब दोनों बाकी प्रस्तावित संशोधन बिलों को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को 33 आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस जारी थी। विपक्ष इस संशोधन में शामिल परिसीमन को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा था। दरअसल, दक्षिण भारत के उन राज्यों में इसको लेकर खासा विरोध था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करके आर्थिक विकास को प्राथमिकता बनाया था। उनकी आशंका थी कि परिसीमन विधेयक के अस्तित्व में आने से संसद में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विपक्ष में का आरोप है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित करने का उपक्रम महज कुछ राज्यों में हो रहे चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिये था। ताकि महिला वोटरों को लुभाया जा सके। विपक्ष ने संसद में जारी बहस के बीच कानून मंत्रालय द्वारा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने के लिये अधिसूचना जारी करने पर भी सवाल उठाये। उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण कानून का उद्देश्य संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रावधान था। मगर राजग सरकार ने प्रस्तावित 131वें संविधान बिल 2026 में सीटों में आरक्षण को परिसीमन के आधार पर लागू करने की बात कही थी। दरअसल, विपक्ष इस संशोधन बिल की टाइमिंग और आरक्षण को परिसीमन के आधार पर लागू करने की शर्त पर सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि 33 फीसदी आरक्षण को लोकसभा की मौजूदा सीटों के आधार पर ही लागू करना चाहिए। विपक्ष परिसीमन से उपजी विसंगतियों और दक्षिण के राज्यों की चिंताओं को तरजीह देने की बात करता रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की दलील रही कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। बिल का मकसद महिला सशक्तीकरण ही है। जिसके लिये इसके लागू करने के तरीके का विरोध किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की दलील थी कि परिसीमन संविधान सम्मत है और बढ़ती आबादी के बाद सीटों को तार्किक बनाये जाने की जरूरत है। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से एससी-एसटी के हितों के पैरोकार होने की दलीलें भी दी गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर उत्तर-दक्षिण का नैरेटिव गढ़ने का आरोप भी लगाया। साथ ही विपक्ष को महिलाओं के आक्रोश की कीमत चुकाने की भी चेतावनी दी। वहीं विपक्ष ने केंद्र पर देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ये संशोधन दलित व पिछड़े वर्गों के हित में नहीं है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाये गए कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन करना कितना न्यायसंगत है। इसके लिये नये जनगणना के आंकड़े आने का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन को संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला बताया। उन्होंने महिला आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ने की तार्किकता को लेकर भी सवाल उठाया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को खारिज किया कि निर्णय प्रक्रिया किसी भी तरह किसी के साथ भेदभाव करेगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन पहले के अनुपात के अनुसार ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 33 फीसदी महिलाओं को यहां आने दें और उन्हें निर्णय करने दें।

विकास और सुशासन के मुद्दों पर भी काम करे मीडिया

> “ भारत जैसे विविधता और बहुलता भरे समाज में सभी उम्मीदों, सपनों और बदलावों को रेखांकित कर पाना कठिन है। क्योंकि विकास के अनेक तल हैं और देश में समाज की रचना भी बहुस्तरीय है, देश में कहावत प्रचलित है ‘चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर वाणी‘, इसलिए किसी राज्य को भी एक ही पैमाने से नहीं नापा जा सकता।

मीडिया की ताकत आज सर्वव्यापी है और कई मायनों में सर्वग्रासी भी। ऐसे में विकास के सवालों और उसके लोकव्यापीकरण में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो उठी है। यह एक ऐसा समय है, जबकि विकास और सुशासन के सवालों पर हमारी राजनीति में बात होने लगी है, तब मीडिया में यह चर्चाएं न हों यह संभव नहीं है। समाज विकास की प्रक्रिया और उसकी आकांक्षाएं मीडिया में दर्ज हों, ऐसी उम्मीद की जाती है। इन विषयों की रिपोर्टिंग के लिए तमाम पत्रकार आगे आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी विकास की पत्रकारिता को एक नई नजर से देखा जा रहा है। भारत में विकास की पत्रकारिता और उसके सवालों से जूझने के लिए पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी तैयार है, किंतु मुख्यधारा के मीडिया के द्वारा इन विषयों को तरजीह न दिए जाने के कारण निराशा ही हाथ लगती है। संकट पत्रकारों की ओर से नहीं, मीडिया संस्थानों और प्रबंधकों की ओर से है। विकास का मुद्दा क्या सिर्फ सरकारी विज्ञापनों का विषय है, सरकारी मीडिया का विषय है, या यह समाज में हो रहे नवाचारों का भी विषय है। विकास पत्रकारिता को पाठ्यक्रम के साथ मीडिया कर्म का भी हिस्सा होना चाहिए।भारत जैसे विविधता और बहुलता भरे समाज में सभी उम्मीदों, सपनों और बदलावों को रेखांकित कर पाना कठिन है। क्योंकि विकास के अनेक तल हैं और देश में समाज की रचना भी बहुस्तरीय है, देश में कहावत प्रचलित है ‘चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर वाणी‘, इसलिए किसी राज्य को भी एक ही पैमाने से नहीं नापा जा सकता। जैसे मध्य प्रदेश में एक तरफ समृद्ध मालवा है, तो दूसरी ओर झाबुआ जैसे इलाके भी हैं। एक तरफ इंदौर की चमक है, तो दूसरी ओर अलीराजपुर जैसे क्षेत्र भी हैं। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ है, तो भिलाई भी है। ऐसे में पत्रकारों या विकास के सवालों पर लिखने वालों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह विकास की भूमिका भी यहां विस्तृत और परिवर्तित

हो जाती है। हम देखें तो 1950 के पहले आर्थिक विकास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। किंतु 1950 के बाद की चिंताएं अलग हो गयी। बाद के दिनों में सामाजिक विकास को एक बड़ा कारक माना जाने लगा है। सामाजिक न्याय से लेकर स्थाई विकास के सवाल अब बड़े हो गए हैं। यहां तक कि पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें भी हमारे सामने हैं।

एक समय में विकसित और विकासशील देशों की बहसें भी हमने सुनीं जिनमें मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट एक अलग तरह से बात करती हुयी नजर आती है, जिनमें कुछ सवाल आज भी मौजू हैं। नियंत्रित मीडिया से मीडिया के चौतरफा विकास का समय भी आया जिसमें कुछ भी छिपाना और दबाना असंभव सा हो गया। कई बार यह भी लगता रहा कि विकास का सवाल सिर्फ सरकारी माध्यमों (मीडिया) के लिए ही महत्व का है, बाकी माध्यमों का अपना एजेंडा और राय अलग है। यहां यह भी देखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन(संचार) सिर्फ सूचनाओं का हस्तांतरण नहीं है। बल्कि पक्षधरता के साथ, न्याय के लिए खड़ा होना भी है। जन को ताकतवर बनाना भी है। अवसर की समानता की अवधारणा को प्रचारित और स्थापित करना भी है।

विकेन्द्रीकरण ने विकास के सामने कई नए प्रश्न खड़े किए हैं। जिनके भी ठोस और वाजिब हल हमें ढूंढने चाहिए। जैसे पंचायती राज में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। सत्ता इसके चलते पंचायतों तक पहुंची, पर सवाल यह है कि क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है? क्या संसदीय राजनीति और चुनावों की तमाम बुराईयां हमारी पंचायतों तक नहीं पहुंच गयी? वहीं हम मीडिया को देखें तो उसका भी विस्तार हुआ है। व्यापकता बढ़ी है, पहुंच भी बढ़ी है। पर सवाल यह है कि क्या मीडिया में संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता और विविधता को आदर देने की उसकी भावना भी बढ़ी है, तो शायद उत्तर नकारात्मक ही हो। तीनों तंत्रों (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) से निराश लोग मीडिया की ओर बहुत उम्मीदों से देखते हैं। कई अर्थों में सत्ता का तो विकेन्द्रीकरण दिखता है, किंतु मीडिया धीरे-धीरे केन्द्रीकरण का शिकार हो रहा है। इसलिए जरूरी है क्रास मीडिया ओनरशिप के बारे में भी भारत जैसे देश सोचें। ताकि मीडिया के एकाधिकार के खतरों से बचा जा सके। इसके साथ ही प्रेस कौंसिल जैसी नख-दंत हीन संस्था के अधिकारों और क्षेत्राधिकार में बदलाव करते हुए उसे मीडिया कौंसिल में बदला जाना जरूरी है ताकि वह आज के प्रभावी मीडिया को भी अपनी चर्चा में ले सके। हम जिस संकट से दो चार हैं, वह यह है कि सूचनाएं बढ़ गई हैं और खबरें घट गई हैं। अखबारों के पन्ने बढ़ गए हैं, किंतु इनसे आम-आदमी गायब है। चैनल अब चौबीस घंटे कुछ बोलते हैं, पर उनमें विकास और जनता के सवालों की जगह बहुत कम है। जबकि विकास की पत्रकारिता की मुक्ति इसमें है कि जो लोग मीडिया तक नहीं पहुंच सकते, मीडिया उन तक पहुंचे। उनका दर्द सुने। अच्छी और उम्मीद जगाने वाली खबरों की ओर जाएं।

हमारी राजनीति बदल रही है, हमारा समाज बदल रहा है किंतु हमारे मीडिया के सोचने और अभिव्यक्त करने की शैली उस तुलना में नहीं बदली जैसी बदलनी चाहिए। आज यह मान्यता बन चुकी है कि विकास भारतीय मीडिया की प्राथमिकता नहीं है, शायद समाज भी उसकी प्राथमिकता नहीं है। हमारे नागरबोध ने मीडिया को समाज से बड़ा बना दिया है। किंतु यह तय मानिए कि कोई भी मीडिया, कोई भी राजनीति और कोई भी व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं हो सकता। 18 से 25 साल और 18 से 35 साल के युवाओं के बीच बाजार खोज रहे मीडिया की चिताएं अलग हो सकती हैं किंतु समाज की चिताएं कुछ भिन्न हैं। वे ही वास्तविक चिंताएं हैं। मीडिया अगर इन चिंताओं से अलग व्यवहार कर रहा है तो वह अपने अस्तित्व पर संकट स्वयं रच है। विश्वसनीयता और प्रामणिकता के संकट तो उसके साथ संयुक्त हैं ही। मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के लिए यह सोचने का सही समय है कि जब सारा देश विकास और सुशासन के सवालों पर गंभीर हो रहा है, उसमें अपने शासकों से जवाब मांगने की हिम्मत आ रही है, तो हमारा मुख्यधारा का मीडिया क्या कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के सामने आज उपस्थिति हैं, अगर इन सवालों के हल हमने आज नहीं तलाशे तो कल बहुत देर हो जाएगी।

प्रेरणा

दृढ़ निश्चय की ज्योति: जब संकल्प ने रच दिया अमर इतिहास

मानव जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं, जब परिस्थितियाँ व्यक्ति की क्षमता को चुनौती देती हैं और उसी समय यह तय होता है कि वह साधारण रहेगा या असाधारण बन जाएगा। इतिहास गवाह है कि महानता कभी सहज रास्तों से नहीं आती, बल्कि वह कठिनाइयों से जूझते हुए, सीमाओं को पार करते हुए और स्वयं पर अटूट विश्वास रखते हुए हासिल की जाती है। इसी सत्य को अपने जीवन से सिद्ध करने वाले महान साहित्यकार Munshi Premchand का जीवन हमें यह सिखाता है कि संकल्प यदि सच्चा हो तो भाषा, परिस्थिति और संसाधनों की सीमाएँ भी उसके आगे झुक जाती हैं।

प्रेमचंद का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वे पहले उर्दू में लिखते थे और ‘नवाब राय’ नाम से अपनी रचनाएँ प्रकाशित करते थे। उस समय हिंदी भाषा से उनका कोई विशेष परिचय नहीं था। लेकिन जब उनके उर्दू कहानी संग्रह ‘सोज-ए-वतन’ पर अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया, तब यह घटना उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ बन गई। यह केवल एक पुस्तक पर लगी पाबंदी नहीं थी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनौती देने वाली घटना थी। ऐसे समय में बहुत से लोग निराश होकर लेखन छोड़ सकते थे, लेकिन प्रेमचंद ने इसे एक अवसर के रूप में लिया—अपने आपको एक नई दिशा देने का अवसर।

उन्होंने न केवल अपना नाम ‘नवाब राय’ से बदलकर ‘प्रेमचंद’ रखा, बल्कि यह भी संकल्प लिया कि अब वे केवल हिंदी में ही लेखन करेंगे। यह निर्णय जितना सरल सुनने में लगता है, वास्तव में उतना ही कठिन था, क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान लगभग नहीं था। जब उनके एक साहित्यिक मित्र ने उनसे यह प्रश्न किया कि बिना हिंदी जाने वे इसमें कैसे लिख पाएंगे, तब प्रेमचंद का उत्तर उनके अद्भुत आत्मविश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उर्दू और हिंदी में मूलभूत अंतर नहीं है, केवल लिपि का फर्क है, और यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। यही वह क्षण था, जब संकल्प ने आकार लेना शुरू किया। प्रेमचंद ने देवनागरी लिपि सीखने का निश्चय किया और पूरे मनोयोग से उसे सीखने में जुट गए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह काम कितना कठिन है या इसमें कितना समय लगेगा, बल्कि उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। यही एकाग्रता और दृढ़ता उन्हें उस मुकाम तक ले गई, जहाँ वे हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष बनकर उभरे।

उनकी यह यात्रा केवल भाषा बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास की एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है—संकल्प। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए, तो वह किसी भी कमी को अपनी ताकत में बदल सकता है।

प्रेमचंद ने हिंदी में जो रचनाएँ दीं, वे आज भी समाज का आईना मानी जाती हैं। उनका उपन्यास ‘गोदान’ केवल एक साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन की गहराइयों को उजागर करने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। उनकी कहानियाँ सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं और जीवन के संघर्षों को इतनी सहजता और प्रभावशीलता से प्रस्तुत करती हैं कि पाठक उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। यह सब संभव हुआ केवल इसलिए, क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प को कभी डगमगाने नहीं दिया।

उनकी सफलता यह भी सिखाती है कि किसी भी नई शुरुआत के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पहले से सभी आवश्यक कौशल हों। कई बार हमें रास्ते में सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। यदि हम यह सोचकर रुक जाएँ कि हमें अभी सब कुछ नहीं आता, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि हम यह विश्वास रखें कि हम सीख सकते हैं, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह जाता।

आज के समय में, जब लोग छोटी-छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तब प्रेमचंद का जीवन एक मार्गदर्शक की तरह हमारे सामने खड़ा होता है। वह हमें याद दिलाता है कि सफलता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास का फल होती है। संकल्प ही वह शक्ति है, जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रेमचंद ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए लिखा। उनका लेखन समाज की समस्याओं को उजागर करने और उनमें सुधार लाने का एक माध्यम बना। उन्होंने अपनी कलम को समाज की सेवा का साधन बनाया, और यही कारण है कि उनकी रचनाएँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है, जो केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी हो।

अंततः, प्रेमचंद का जीवन यह संदेश देता है कि यदि हमारे भीतर सच्चा संकल्प है, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चाहे वह भाषा की हो, परिस्थितियों की हो या संसाधनों की कमी की—संकल्प की शक्ति के सामने सब कुछ छोटा पड़ जाता है। जरूरत केवल इस बात की है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानें, उस पर विश्वास रखें और पूरे मन से उसके लिए प्रयास करें।

इस प्रकार, “संकल्प से सफलता” केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। प्रेमचंद की यह प्रेरणादायक यात्रा हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब मन में दृढ़ निश्चय हो, तो असंभव भी संभव बन जाता है और साधारण जीवन भी एक असाधारण कहानी में बदल सकता है।

लाल गलियारे का अंत: शाह की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति ने रची सुरक्षा की नई इबारत

भारत की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में यदि किसी एक समस्या ने दशकों तक देश की प्रगति को बाधित किया और हजारों निर्दोषों का लहू बहाया, तो वह नक्सलवाद था। एक समय ऐसा भी था जब तत्कालीन सरकारों ने इसे देश के लिए ‘सबसे बड़ा खतरा’ स्वीकार किया था, लेकिन इसके समाधान के लिए वह ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई थी जो आज नजर आ रही है। आज जब हम 2026 के मुहाने पर खड़े हैं, तो भारत के नक्शे से ‘लाल गलियारे’ का सिकुड़ता दायरा और बस्तर के जंगलों में गूंजती शांति इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति ने इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है।अमित शाह ने गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही नक्सलवाद को केवल एक स्थानीय कानून-व्यवस्था की समस्या मानने के बजाय इसे एक राष्ट्रव्यापी सुरक्षा चुनौती के रूप में चिन्हित किया और इसे समाप्त करने के लिए ‘समाधान’ और ‘लौह प्रहार’ जैसी रणनीतियों का सूत्रपात किया। अमित शाह की कार्यशैली का सबसे प्रमुख पहलू उनका ‘परिणाम-आधारित’ दृष्टिकोण है। उन्होंने अपने विभिन्न भाषणों में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि नक्सलवाद का अस्तित्व केवल बंदूकों के दम पर नहीं, बल्कि विकास की कमी और वैचारिक भ्रम के कारण टिका हुआ था। शाह ने उन ‘अर्बन नक्सल’ समूहों को भी बेनकाब किया जो शहरों में बैठकर जंगलों में हिंसा फैलाने वालों के लिए वैचारिक कवच तैयार करते थे। गृह मंत्री का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और यदि कोई समूह हथियार उठाकर संविधान को चुनौती देता है, तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना राज्य का उत्तरदायित्व है। इसी सोच के तहत उन्होंने सुरक्षा बलों को वह ‘फ्री हैंड’ दिया, जिसकी मांग वे दशकों से कर रहे थे। आज सुरक्षा बल न केवल नक्सलियों के गढ़ों में घुसकर प्रहार कर रहे हैं, बल्कि उन दुर्गम इलाकों में भी तिरंगा फहरा रहे हैं जहाँ पहले जाना असंभव माना जाता था। पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में सैकड़ों नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। इन कैंपों ने नक्सलियों की रसद, सूचना तंत्र और छिपने के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अमित शाह ने व्यक्तिगत रूप से इन क्षेत्रों का दौरा कर जवानों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें आधुनिक तकनीक, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और संचार के बेहतर साधनों से लैस किया। गृह मंत्री ने संसद में स्पष्ट किया था कि जब तक अंतिम नक्सली हथियार नहीं डाल देता या उसका सफाया नहीं हो जाता, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। अमित शाह की रणनीति केवल सैन्य कार्यवाही तक सीमित नहीं रही है। उनके भाषणों का एक बड़ा हिस्सा ‘विकास’ को समर्पित रहा है। उनका तर्क है कि जहाँ सड़क पहुँचती है, वहाँ नक्सलवाद पीछे हट जाता है। इसी सोच के साथ उन्होंने सड़क संपर्क परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल उन इलाकों में बिछाया गया जहाँ कभी नक्सलियों का खौफ हुआ करता था। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। एकलव्य मॉडल स्कूलों के माध्यम से जनजातीय बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना और मोबाइल टावरों के जरिए डिजिटल इंडिया को घने जंगलों तक पहुँचाना शाह के ‘सर्वांगीण विकास’ मॉडल का हिस्सा है। जब एक आदिवासी युवक के हाथ में बंदूक के बजाय स्मार्टफोन और रोजगार के अवसर आए, तो नक्सलियों की भर्ती प्रक्रिया स्वतः ही ध्वस्त हो गई।

अमित शाह ने बार-बार एक और महत्वपूर्ण बात कही है—'संवाद और पुनर्वास’। उन्होंने उन युवाओं के लिए हमेशा ‘लाल कालीन’ बिछाई है जो गुमराह होकर हिंसा की राह पर चले गए थे। सरकार की आत्मसमर्पण नीति को इतना आकर्षक और सुलभ बनाया गया कि हजारों नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। शाह ने अपने भाषणों में स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है जो भटक गए हैं, लेकिन जो निर्दोषों की हत्या और विकास कार्यों में बाधा डालेंगे, उन्हें सुरक्षा बलों के लौह प्रहार का सामना करना पड़ेगा। यह ‘कैरेट एंड स्टिक’ (पुरस्कार और दंड) की नीति ही थी जिसने नक्सली संगठनों के भीतर दरार पैदा कर दी और उनके नेतृत्व को कमजोर कर दिया।

आज झारखंड का ‘बूढ़ा पहाड़’ हो या छत्तीसगढ़ का ‘अबूझमाड़’, इन क्षेत्रों की पहचान अब आतंक के बजाय प्रगति से होने लगी है। अमित शाह ने सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों और खुफिया एजेंसियों के बीच जिस तरह का समन्वय स्थापित किया, वह प्रशासनिक कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने ‘यूनिफाइड कमांड’ के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान को तेज किया, जिससे ऑपरेशन की सटीकता बढ़ी और सुरक्षा बलों के हताहत होने की दर में भारी कमी आई।

अमित शाह का योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में एक ऐसे सेनापति के रूप में देखा जाएगा जिसने देश की आंतरिक एकता को खंडित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल नक्सलियों को हराया है, बल्कि उन लाखों लोगों के मन में विश्वास जगाया है जो दशकों तक डर और अभाव के साये में जीने को मजबूर थे। आज का भारत अब ‘लाल गलियारे’ के अंत का जश्न मना रहा है और विकास के नए क्षितिज की ओर अग्रसर है, जहाँ गोलियों की जगह कलम होगी और भय की जगह स्वाभिमान होगा।

अभियान

“हिमालय की पुकार: चारधाम यात्रा 2026 में आत्मा का परम मिलन”

जब धरती और आकाश के बीच खड़े हिमालय अपनी श्वेत चादर ओढ़े मौन साधना में लीन रहते हैं, तब उन्हीं ऊंचाइयों के बीच एक ऐसी दिव्य पुकार गूंजती है जो हर श्रद्धालु के हृदय को स्पर्श करती है। यह पुकार है चारधाम यात्रा की—एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा, जो केवल कदमों से नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और समर्पण से पूरी होती है। वर्ष 2026 में यह पावन यात्रा 19 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है, और यह दिन भी कोई साधारण नहीं, बल्कि अक्षय तृतीया का शुभ अवसर है, जिसे सनातन परंपरा में अनंत फल देने वाला माना गया है।

चारधाम यात्रा का नाम सुनते ही मन में जिन चार पवित्र स्थलों की छवि उभरती है, वे हैं—यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। ये केवल चार मंदिर नहीं, बल्कि चार ऐसे आध्यात्मिक द्वार हैं, जिनसे होकर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है। कहा जाता है कि इन चारों धामों के दर्शन करने वाला व्यक्ति जीवन के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है।

हिमालय की गोद में बसा यमुनोत्री धाम इस यात्रा का प्रथम पड़ाव है। यहां पहुंचते ही ऐसा अनुभव होता है मानो प्रकृति स्वयं मां के रूप में भक्तों का स्वागत कर रही हो। मां यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति के दर्शन करते समय मन स्वतः ही शांत हो जाता है। यहां के गर्म जलकुंड, बर्फ से ढकी चोटियां और निर्मल वातावरण मनुष्य के भीतर के विकारों को धोने का कार्य करते हैं। श्रद्धालु जब यहां पहुंचता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक चेतना है, जो ईश्वर की ओर बढ़ रही है।

इसके बाद गंगोत्री धाम आता है, जहां मां गंगा का उद्गम माना जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवनधारा है। यहां के दर्शन करते समय ऐसा लगता है जैसे हर लहर में ईश्वर का आशीर्वाद बह रहा हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर अवतरित किया था। गंगोत्री में जब भक्त गंगा जल को अपने मस्तक पर लगाता है, तो वह केवल जल नहीं, बल्कि दिव्यता का स्पर्श होता है, जो उसके मन और आत्मा को शुद्ध कर देता है।

जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, मार्ग कठिन होता जाता है और यही कठिनाई भक्ति की सच्ची परीक्षा भी बन जाती है। केदारनाथ धाम इस यात्रा का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहां भगवान शिव का निवास है, जो बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि तप, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है कि महाभारत के पश्चात पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहां भगवान शिव की आराधना की थी। जब श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर केदारनाथ पहुंचता है, तो उसकी हर सांस में केवल एक ही नाम होता है—हर हर महादेव। उस क्षण उसे यह अनुभव होता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो सच्चे मन से प्रयास करता है, उसके लिए हर बाधा स्वयं हट जाती है।

अंततः यात्रा का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु नर-नारायण रूप में विराजमान हैं। यह स्थान ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का संगम है। यहां की अखंड ज्योति, अलकनंदा नदी का कल-कल प्रवाह और मंदिर की भव्यता मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन के बिना चारधाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहां पहुंचकर भक्त को यह अनुभूति होती है कि उसकी यात्रा पूर्ण हो गई है और वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य के करीब पहुंच गया है। चारधाम यात्रा केवल भौतिक दूरी तय करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि हमारा संकल्प अडिग हो और विश्वास दृढ़ हो, तो हम हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। हिमालय की कठिन राहें हमें धैर्य, संयम और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती हैं। हर मोड़ पर प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि हम केवल एक यात्री हैं, और हमारा अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है।

इस यात्रा में जाने से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक है। ऊंचाई, ठंड और कठिन मार्ग के कारण कई चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन जब मन में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो ये सभी कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। यात्रा के दौरान सादगी, अनुशासन और श्रद्धा का पालन करना ही सबसे बड़ा साधन है। यह यात्रा हमें बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर झांकने का अवसर देती है, जहां हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है।

चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब मनुष्य अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह को त्यागकर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है।

वर्ष 2026 की यह चारधाम यात्रा हर श्रद्धालु के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर शुरू होने वाली यह यात्रा हमें यह संदेश देती है कि यदि हमारे भीतर सच्ची आस्था और अटूट विश्वास है, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

अंत में, जब कोई श्रद्धालु इस यात्रा को पूर्ण करता है, तो वह केवल चार मंदिरों के दर्शन करके नहीं लौटता, बल्कि वह एक नए जीवन, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ लौटता है। उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसका मन शांत हो जाता है और उसका जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। यही चारधाम यात्रा की महिमा है—एक ऐसी यात्रा, जो हमें स्वयं से मिलाती है, ईश्वर से जोड़ती है और जीवन के सच्चे अर्थ को समझाती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

'चाय पर संवाद' से चुनावी रणभूमि में उतरी भाजपा: सूरत में जगदीश विश्वकर्मा ने कार्यकर्ताओं को सिखाया जीत का गणित

सूरत। गुजरात के राजनीतिक माहौल में चुनावी हलचल तेज होते ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है, और इसी कड़ी में सूरत नगर निगम चुनाव से पहले अडाजन क्षेत्र में आयोजित 'चाय पर संवाद' कार्यक्रम ने पार्टी के जमीनी अभियान को एक नई दिशा दे दी है। इस कार्यक्रम में गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने न केवल कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, बल्कि उन्हें एक शिक्षक की तरह चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और मतदाताओं तक पहुंचने के व्यावहारिक तरीके भी सिखाए। पूरे कार्यक्रम का माहौल ऐसा रहा, जैसे किसी कक्षा में गुरु अपने शिष्यों को जीत का सूत्र समझा रहा हो।
कार्यक्रम का केंद्र केवल भाषण या औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से एक इंटरैक्टिव प्रशिक्षण सत्र में बदल गया, जहां कार्यकर्ताओं को सिर्फ सुनने के बजाय सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं के साथ हुए संवाद ने इस कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बना दिया। जगदीश विश्वकर्मा ने उनसे सीधे सवाल पूछे—सरकारी योजनाओं की जानकारी, उनके लाभार्थियों तक पहुंचने के तरीके और जमीनी स्तर पर काम करने की चुनौतियों को लेकर—ताकि यह परखा जा सके कि संगठन की नीतियां वास्तव में जनता तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज की राजनीति केवल नारों और भाषणों तक सीमित नहीं रह गई है। चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि कार्यकर्ता योजनाओं को कागज से निकालकर लोगों के जीवन तक पहुंचाएं। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और अन्य महिला एवं जनकल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे संपर्क बनाना ही असली चुनावी ताकत है। उनका जोर इस बात पर था कि जब कार्यकर्ता लाभार्थियों के अनुभव और संतुष्टि को समझेंगे, तभी वे मतदाताओं के साथ एक भरोसेमंद रिश्ता बना पाएंगे।
इस प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू डेटा आधारित रणनीति पर दिया गया जोर रहा। जगदीश विश्वकर्मा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र के लाभार्थियों की सूची तैयार रखें और मतदाताओं से बातचीत के दौरान तथ्यों और आंकड़ों के साथ संवाद करें। उन्होंने इसे आधुनिक चुनावी राजनीति का अनिवार्य हिस्सा बताते हुए कहा कि अब चुनाव केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि जानकारी और विश्वास के संयोजन से जीते जाते हैं। यह दृष्टिकोण पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को तकनीकी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत भी देता है।
कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत में उठे मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय सक्रिय नजर आते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे साल जनता के बीच रहकर सेवा और संपर्क बनाए रखते हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं में यह विश्वास जगाने की कोशिश की कि उनकी निरंतर मेहनत ही चुनावी जीत की असली नींव है।
इस पूरे आयोजन में महिला मोर्चा की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया। जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संगठन को मजबूती देने और समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अधिक से अधिक मतदाताओं तक पार्टी की योजनाओं और नीतियों को पहुंचाएं।
'चाय पर संवाद' जैसे सरल लेकिन प्रभावी मंच के जरिए पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह चुनावी तैयारी को केवल बड़े-बड़े रैलियों या भाषणों तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि जमीनी स्तर पर छोटे-छोटे समूहों में संवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। यह रणनीति न केवल संगठन को मजबूत करती है, बल्कि कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करती है।
सूरत नगर निगम चुनाव के मद्देनजर यह कार्यक्रम एक संकेत है कि आने वाले दिनों में चुनावी मुकाबला और भी तेज और रणनीतिक होने वाला है। जहां एक ओर राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम यह दर्शाते हैं कि अब चुनाव केवल प्रचार नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित अभियान बन चुका है, जिसमें हर कार्यकर्ता एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा है।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाएगी 05 जोड़ी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर 05 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09087/09088 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [12 फेरे]

- ट्रेन संख्या 09087 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद स्पेशल प्रत्येक बुधवार को 23:20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन 07:20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन 22 अप्रैल से 27 मई, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09088 अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 22:40 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान कर अगले दिन 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 23 अप्रैल से 28 मई, 2026 तक चलेगी।
- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत एवं वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी।
- इस ट्रेन में प्रथम एसी, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09085/09086 मुंबई सेंट्रल – इंदौर एसी सुपरफास्ट द्वि-साप्ताहिक स्पेशल [24 फेरे]

- ट्रेन संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल – इंदौर स्पेशल प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को 23:20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन 13:00 बजे इंदौर पहुंचेगी। यह ट्रेन 20 अप्रैल से 29 मई, 2026 तक चलेगी।
- इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09086 इंदौर – मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को 17:00 बजे इंदौर से प्रस्थान कर अगले दिन 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 अप्रैल से 30 मई, 2026 तक चलेगी।
- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, दाहोद, रतलाम एवं उज्जैन स्टेशनों पर ठहरेगी।
- इस ट्रेन में प्रथम एसी, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09053/09054 उधना – सांतरागाछी स्पेशल [04 फेरे]

- ट्रेन संख्या 09053 उधना – सांतरागाछी स्पेशल सोमवार, 20 अप्रैल, 2026 एवं शनिवार, 25 अप्रैल, 2026 को 11:25 बजे उधना से प्रस्थान कर अगले दिन 21:00 बजे सांतरागाछी पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09054 सांतरागाछी – उधना स्पेशल बुधवार, 22 अप्रैल, 2026 एवं सोमवार, 27 अप्रैल, 2026 को 00:05 बजे सांतरागाछी से प्रस्थान कर अगले दिन 10:00 बजे उधना पहुंचेगी।
- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नंदुरबार, भुसावल, बडनेरा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर एवं खड़गपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।
- इस ट्रेन में स्लीपर एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 09061/09062 उधना – जयनगर अनारक्षित स्पेशल [02 फेरे]

- ट्रेन संख्या 09061 उधना – जयनगर स्पेशल रविवार, 19 अप्रैल, 2026 को 01:30 बजे उधना से प्रस्थान कर अगले दिन 13:50 बजे जयनगर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09062 जयनगर – उधना स्पेशल सोमवार, 20 अप्रैल, 2026 को 15:05 बजे जयनगर से प्रस्थान कर अगले दिन 06:15 बजे उधना पहुंचेगी।
- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में चलथान, बारडोली, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छेओकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, दिलदारनगर, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, सकरी एवं मधुबनी स्टेशनों पर ठहरेगी।
- इस ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

5. ट्रेन संख्या 09067/09068 उधना – मधुबनी अनारक्षित स्पेशल [02 फेरे]

- ट्रेन संख्या 09067 उधना – मधुबनी स्पेशल रविवार, 19 अप्रैल, 2026 को 05:30 बजे उधना से प्रस्थान कर अगले दिन 19:00 बजे मधुबनी पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09068 मधुबनी – उधना स्पेशल सोमवार, 20 अप्रैल, 2026 को 20:00 बजे मधुबनी से प्रस्थान कर बुधवार को 09:35 बजे उधना पहुंचेगी।
- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में चलथान, बारडोली, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छेवकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा एवं सकरी स्टेशनों पर ठहरेगी।
- इस ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।
- ट्रेन संख्या 09053 की बुकिंग प्रारंभ है, जबकि ट्रेन संख्या 09087, 09088, 09085 एवं 09086 की बुकिंग 19.04.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सूरत में जल संकट की दस्तक: 20 अप्रैल को रांदेर अडाजन में कई घंटों तक बंद रहेगी पानी सप्लाई

सूरत। गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहर सूरत में एक बार फिर पानी की सप्लाई को लेकर बड़ी असुविधा की स्थिति बनने जा रही है। शहर के रांदेर और अडाजन क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों को 20 अप्रैल 2026, सोमवार की शाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जरूरी तकनीकी कार्य के चलते कुछ घंटों के लिए जल आपूर्ति पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह कदम भले ही अस्थायी असुविधा पैदा करेगा, लेकिन नगर निगम के अनुसार इसका उद्देश्य भविष्य में पानी की सप्लाई को और अधिक सुचारु और प्रभावी बनाना है।
नगर निगम के हाइड्रोलिक विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रांदेर क्षेत्र के जोगनी नगर वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के तहत अडाजन स्थित स्टेशन से पानी के प्रेशर को बेहतर करने के लिए मुख्य कॉमन हेडर लाइन से जुड़े पाइपलाइन सिस्टम में नए वाल्व लगाए जाएंगे। इसके साथ ही टैंक को तेजी और संतुलित तरीके से भरने के लिए राइजिंग मेन लाइन को जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में पानी की आपूर्ति अधिक स्थिर और नियंत्रित हो सकेगी। तकनीकी रूप से यह एक महत्वपूर्ण सुधार कार्य है, लेकिन इसके चलते फिलहाल आम लोगों को असुविधा झेलनी पड़ेगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 अप्रैल की शाम 5:30 बजे से रात 8:50 बजे तक पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। हालांकि यह समय सीमा करीब साढ़े तीन घंटे की है, लेकिन नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ इलाकों में पानी का प्रेशर पहले से ही कम हो सकता है और सप्लाई सामान्य होने में थोड़ा अतिरिक्त समय भी लग सकता है। यानी असर केवल निर्धारित समय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उससे पहले और बाद में भी लोगों को पानी की कमी महसूस हो सकती है। इस जल कटौती का असर रांदेर और अडाजन क्षेत्र की बड़ी संख्या में सोसाइटियों और रिहायशी इलाकों पर पड़ेगा।
जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है, उनमें मेरुलक्ष्मी सोसाइटी, रंगअवधूत सोसाइटी सेक्शन-3, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, सुमन संध्या आवास, हयात रेजीडेंसी, रॉयल हेरिटेज, कॉजवे के आसपास की सोसाइटियां, शाश्वत कॉम्प्लेक्स, गोविंदनगर, सहजधाम, वसंत विहार, परशुराम गार्डन, एल.पी. सवाणी स्कूल क्षेत्र, सुमन विहार, मिलन पार्क, ग्रीन वैली, शुभम पार्क, यमुना कॉम्प्लेक्स, महर्षि अरविंदो सोसाइटी, जलाराम नगर, क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स, अक्षरधाम सोसाइटी, डी-मार्ट क्षेत्र, हरिदर्शन सोसाइटी, उमिया पार्क, आत्मा पार्क, साईं विहार, आशानगर, संस्कार पार्क, हरिओम नगर, श्रीनाथ सोसाइटी, रेवानगर, नवरंग सोसाइटी, कंकूनगर, वेस्टर्न विला, ग्रीन एवेन्यू, टीजीबी रेस्टोरेंट के आसपास के इलाके और कई अन्य आवासीय क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा रांदेर गामताल और आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की सप्लाई बाधित होने या कम प्रेशर की समस्या सामने आ सकती है।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अस्थायी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहले से ही आवश्यक पानी का संग्रह कर लें। खासतौर पर पीने के पानी, खाना बनाने और अन्य जरूरी घरेलू कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जल आपूर्ति बहाल होने के बाद भी कुछ समय तक पानी का उपयोग सावधानीपूर्वक और संयम से करें, ताकि सभी लोगों तक समान रूप से पानी पहुंच सके।

साहित्यिक और सामाजिक योगदान के लिए डॉ. मंजू लोढ़ा को लंदन में प्रतिष्ठित पुरस्कार

मुंबई। लंदन स्थित नेहरू सेंटर में आयोजित *"संवेदनाओं का सफ़र"* शीर्षक से साहित्यिक वार्ता एवं काव्य सत्र एक अविस्मरणीय और भावपूर्ण संध्या के रूप में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में साहित्य, संवाद और संवेदनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने उपस्थित सभी दर्शकों के हृदय को स्पर्श किया।इस गरिमापूर्ण आयोजन में श्री वीरेन्द्र शर्मा, लॉर्ड उदय नगराजु, डॉ. अनुराधा पांडेय, श्री कुलदीप शेखावत, मेयर प्रेरणा, रितु हिंदुजा जैसे अनेक प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति रही। सभी गणमान्य अतिथियों ने लोढ़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. मंजू मंगलप्रभात लोढ़ा के साहित्यिक योगदान और उनकी पुस्तकों पर अपने हृदयस्पर्शी विचार व्यक्त किये, जो उनके लिए अत्यंत भावुक और यादगार क्षण बन गये। समारोह का मुख्य आकर्षण सुप्रसिद्ध साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा के साथ डॉ. मंजू लोढ़ा का संवाद रहा, जिसमें उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा, जीवन के अनुभवों और अपनी लेखनी के पीछे की भावनाओं को साझा किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी दो नई पुस्तकों का प्रीव्यू भी प्रस्तुत किया, जिन्हें दर्शकों से विशेष सराहना मिली। इंदु बारोट ने डॉ. मंजू लोढ़ा की पुस्तकों और काव्य पर अत्यंत सुंदर, गहन और सरस्वती वंदना सदृश भावों से परिपूर्ण अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसने कार्यक्रम की गरिमा को और भी ऊँचाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत धृति बाफना द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। वहीं डॉ. अनीता नायर के प्रभावशाली और सुसंगठित संचालन ने पूरे आयोजन को सहज, गरिमामय और प्रवाहपूर्ण बनाए रखा। यह साहित्यिक संध्या प्रेम, प्रोत्साहन और शब्दों की शक्ति का एक सुंदर उत्सव रही, जिसने सभी को एक सूत्र में बांधते हुए हिंदी साहित्य को वैश्विक मंच पर नई ऊँचाई प्रदान की। अगले दिन आयोजित एक अन्य गरिमामय समारोह में डॉ. मंजू मंगलप्रभात लोढ़ा को उनके साहित्यिक योगदान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार *"IIW She Inspires Awards 2026"* से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके निरंतर समर्पण, साहित्य सेवा और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान का प्रतीक है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव और अधिक बढ़ाया।इस सम्मान समारोह का आयोजन रश्मि द्वारा किया गया।

विश्व धरोहर दिवस पर भावनगर मंडल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन

विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में हेरिटेज म्यूजियम, भावनगर परा में एक भव्य, सुव्यवस्थित एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर एवं हेरिटेज अधिकारी श्री संतोष मिश्रा के नेतृत्व में यांत्रिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी वर्मा, अध्यक्षा, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल थीं। इस अवसर पर संगठन की महिला पदाधिकारी एवं सदस्याएँ भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वर्ष 2026 की थीम "संघर्ष एवं आपदाओं की परिस्थितियों में जीवित धरोहर के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया" के अनुरूप आयोजन में धरोहर संरक्षण के प्रति जागरूकता, उत्तरदायित्व एवं जनसहभागिता पर विशेष बल दिया गया।
अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी वर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक एवं तकनीकी धरोहरें केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, ज्ञान एवं पहचान का आधार हैं। उन्होंने आपदा एवं संकट की परिस्थितियों में धरोहरों के संरक्षण हेतु त्वरित एवं प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शपथ दिलाई।
कार्यक्रम में केन्द्रीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व धरोहर दिवस की थीम पर वक्तृत्व प्रतियोगिता एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वक्तृत्व प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 विद्यार्थियों तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 10 विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा हेरिटेज म्यूजियम, भावनगर परा का अवलोकन भी किया गया। भ्रमण के दौरान संग्रहालय में प्रदर्शित ऐतिहासिक लोकोमोटिव, कोच एवं अन्य धरोहर वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर भारतीय रेल की समृद्ध विरासत को निकट से समझा गया।
कार्यक्रम का संचालन सहायक मंडल यांत्रिक अभियंता श्री विजय भट्ट द्वारा किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहा, बल्कि धरोहर संरक्षण के प्रति जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में भी अत्यंत सफल सिद्ध हुआ।

पश्चिम रेलवे चलाएगी वटवा हावड़ा-वटवा समर स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 09479/09480 वटवा–हावड़ा–वटवा समर स्पेशल ट्रेन को विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:
ट्रेन संख्या 09479 वटवा–हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 20 अप्रैल 2026 एवं 26 अप्रैल 2026 को वटवा से 16:45 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 09:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09480 हावड़ा–वटवा समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 22 अप्रैल 2026 एवं 28 अप्रैल 2026 को हावड़ा से 19:00 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 12:15 बजे वटवा पहुंचेगी। मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन, भरूच जंक्शन, अंकलेश्वर जंक्शन, उधना जंक्शन, नंदुरबार, भुसावल जंक्शन, खंडवा जंक्शन, इटारसी जंक्शन, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया जंक्शन, कोडरमा, धनबाद जंक्शन तथा आसनसोल स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में एसी 1-टियर एसी, 2-टियर एसी, 3-टियर एसी, स्लीपर तथा सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।
ट्रेन संख्या 09479 वटवा–हावड़ा समर स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 19 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।
ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन का संचालन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 09431/09432 साबरमती–आसनसोल–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन (विशेष किराये पर) चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:
ट्रेन संख्या 09431 साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 20 अप्रैल 2026 एवं 26 अप्रैल 2026 को साबरमती से 22:55 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 13:15 बजे आसनसोल पहुंचेगी।
इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09432 आसनसोल–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 22 अप्रैल 2026 एवं 28 अप्रैल 2026 को आसनसोल से 16:20 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 07:15 बजे साबरमती पहुंचेगी।
मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, इडगाह आगरा, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया जंक्शन, कोडरमा तथा धनबाद स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे।
ट्रेन संख्या 09431 साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 19 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।
ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे चलाएगी अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की भीड़ एवं मांग को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

ट्रेन संख्या 09088/09087 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन संख्या 09088 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल (06 ट्रिप) दिनांक 23 अप्रैल से 28 मई 2026 तक प्रति गुरुवार को अहमदाबाद से 22:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन शुक्रवार को 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।
इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09487 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल (06 ट्रिप) दिनांक 22 अप्रैल से 27 मई 2026 तक प्रति बुधवार को मुंबई सेंट्रल से 23:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन गुरुवार को 07:20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।
यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में गेरतपुर, वडोदरा, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर रुकेगी।
इस ट्रेन में एसी 1-टियर, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर श्रेणी के कोच रहेंगे।
ट्रेन संख्या 09088/09087 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 19 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।
ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल ⇌ अहमदाबाद के बीच सुपरफास्ट AC स्पेशल ट्रेन चलाइ जाएगी

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	सेवा के दिन	प्रस्थान	आगमन
09087	मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद	22.04.2026 से 27.05.2026 तक	23:20 बजे (बुधवार)	07:20 बजे (दूसरे दिन)
09088	अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल	23.04.2026 से 28.05.2026 तक	22:40 बजे (गुरुवार)	07:10 बजे (दूसरे दिन)
होल्टः बोरीवली, वापी, सूरत और वडोदरा स्टेशन दोनों दिशाओं में ।				
संरचना: फर्स्ट AC, AC 2-टियर और AC 3-टियर कोच।				

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ऊपर बताई गई ट्रेनों के लिए बुकिंग दि.19.04.2026 से सभी PRS काउंटरों पर और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ट्रेन स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाइ जाएगी ।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक और फॉलो करें:
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें ।

पश्चिम रेलवे
ई–निविदा सूचना
संख्या : EL/TRD/58/2026-27/02
दिनांक : 15.04.2026, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु IREPS पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करते हैं : **निविदा क्रमांक** : EL/TRD/58/2026-27/02, **कार्य का नाम** : TRD work in connection with TJP Yard Remodeling with additional loop line under Simhastha 2028, **अनुमानित लागत** : ₹ 1,40,24,683/-, **बयाना राशि:** ₹ 2,80,500/-, **समापन अवधि** : 18 माह, **निविदा दस्तावेज की राशि** : Nil, **ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय** : 11.05.2026 at 15:00 Hrs., **ऑफर की वैधता** : 60 days from the date of opening, **वेबसाईट** : **www.ireps.gov.in**, **नोटिस बोर्ड** : वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने। ADM/8/1/003
Follow us on: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे
ई–निविदा सूचना
संख्या : EL/TRD/58/2025-26/21RT
दिनांक : 15.04.2026, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु IREPS पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करते हैं : **निविदा क्रमांक** : EL/TRD/58/2025-26/21RT, **कार्य का नाम** : TRD work in connection with BLAX Yard Remodeling with additional loop line under Simhastha 2028, **अनुमानित लागत** : ₹ 1,37,73,083/-, **बयाना राशि:** ₹ 2,75,500/-, **समापन अवधि** : 18 माह, **निविदा दस्तावेज की राशि** : Nil, **ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय** : 14.05.2026 at 15:00 Hrs., **ऑफर की वैधता** : 60 days from the date of opening, **वेबसाईट** : **www.ireps.gov.in**, **नोटिस बोर्ड** : वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने। ADM/8/1/004
Follow us on: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – दाहोद
निविदा सूचना संख्या : M247GLRSEPDM262701
दिनांक : 16.04.2026
कार्य का नाम : 80 इलेक्ट्रिक लोको में EPDM केबल ट्रांझिट तथा प्रोटेक्शन प्रणाली की आपूर्ति तथा स्थापित करना, **पता** : मु.का.प्र./ दाहोद प. रेलवे कार्यालय, **कार्य की अनुमानित लागत** : ₹ 1,52,75,595/-, **बयाना राशि** : ₹ 3,05,600.00/-, **ई–निविदा जमा करने तथा खुलने की दिनांक तथा समय** : ई– निविदा जमा करने की नियत दिनांक तथा समय 08.05.2026 को 14:30 बजे तक तथा ई–निविदा उसी दिन 15:00 बजे खोली जायेगी। Tender Notice and documents available on the website **www.ireps.gov.in**/E-Tenders/Works/ IR Electrical. ADM/7/1/005
Follow us on: twitter.com/WesternRly

“बदलती अर्थव्यवस्था में निवेश का मंत्र: सूरत के इन्वेस्टमेंट फोरम ने दिखाया लंबी सोच का रास्ता”

सूरत, जो देश के सबसे तेजी से उभरते व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों में से एक माना जाता है, वहां शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 को निवेश और आर्थिक समझ को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry द्वारा सरसाना स्थित प्लैटिनम हॉल में ‘इन्वेस्टमेंट फोरम 2.0’ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के उद्योगपतियों, निवेशकों, पेशेवरों और वित्तीय विशेषज्ञों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। यह आयोजन केवल एक सामान्य सेमिनार नहीं था, बल्कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेश की रणनीतियों को समझने और भविष्य की दिशा तय करने का एक गंभीर मंच बनकर उभरा।

कार्यक्रम की शुरुआत चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने बदलती वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दौर में निवेश केवल पैसे लगाने का माध्यम नहीं, बल्कि एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी के विस्तार और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के बीच निवेशकों के लिए सही जानकारी और मार्गदर्शन बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में इस तरह के फोरम निवेशकों को न केवल जागरूक करते हैं, बल्कि उन्हें सही दिशा में निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करते हैं।

इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहे Ridhham Desai, जो Morgan Stanley इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने ‘इंडिया पोस्ट वॉरः टू बी ऑर नॉट टू बी’ विषय पर अपने विचार रखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं और भारत की संभावनाओं का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया इस समय कई तरह की अनिश्चितताओं से गुजर रही है—चाहे वह भू-राजनीतिक तनाव हो, महंगाई का दबाव हो या वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव—लेकिन इन सबके बीच भारत एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है।

रिधम देसाई ने अपने संबोधन में निवेशकों को सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह दी कि वे अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से घबराएं नहीं, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। उनके अनुसार, शेयर बाजार में रोजाना होने वाले उतार-चढ़ाव स्वाभाविक हैं, लेकिन जो निवेशक धैर्य रखते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, वही वास्तविक लाभ प्राप्त करते हैं। उन्होंने भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति, डिजिटल क्रांति और मजबूत आर्थिक ढांचे को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है।

उन्होंने विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया कि टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और एनर्जी मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र आने वाले समय में निवेश के लिए सबसे अधिक संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। इन क्षेत्रों में हो रहे लगातार विकास और सरकारी नीतियों के समर्थन से निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सफल निवेश के लिए केवल सही सेक्टर चुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और अनुशासित निवेश रणनीति अपनाना भी उतना ही आवश्यक है।

कीनोट सत्र के बाद आयोजित पैनल चर्चा ने कार्यक्रम को और भी रोचक और उपयोगी बना दिया। इस चर्चा में Govind Parikh, फाउंडर, गोविंद पारिख सिक्योरिटीज ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने निवेश के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि अक्सर निवेशक बाजार की हलचल से प्रभावित होकर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। इसके विपरीत, जो निवेशक शांत रहते हैं और अपने निवेश को समय देते हैं, वही अंततः सफल होते हैं।

पैनल चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि आज के समय में निवेश केवल पारंपरिक साधनों तक सीमित नहीं रहा है। नए-नए निवेश विकल्प जैसे म्यूचुअल फंड, डिजिटल एसेट्स और अंतरराष्ट्रीय बाजार भी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी नए निवेश विकल्प में कदम रखने से पहले पूरी जानकारी और जोखिम का आकलन करना बेहद जरूरी है।

कार्यक्रम में चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, सचिव बिजल जरीवाला, ट्रेजरर सीए मितेश मोदी सहित कई प्रमुख उद्योगपति और पेशेवर मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन की महत्ता को और बढ़ा दिया। चैंबर ग्रुप चेयरमैन कमलेश गजेरा ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि निवेशकों के बीच एक ऐसा मंच तैयार करना है जहां वे अपने विचार साझा कर सकें और विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर सकें।

कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट कमेटी के चेयरमैन अयूब याकूब अली ने कीनोट स्पीकर का परिचय कराया, जबकि एडवाइजर केतन दलाल ने पूरे कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित किया। को-चेयरमैन डॉ. राकेश दोशी ने सवाल-जवाब सत्र का संचालन किया, जिसमें उपस्थित निवेशकों और पेशेवरों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस सत्र के दौरान निवेशकों ने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक निवेश से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार से और संतोषजनक उत्तर दिया।

पूरे आयोजन के दौरान एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि आज के समय में निवेश केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी है। सही जानकारी, उचित रणनीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बिना निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। वहीं, यदि निवेशक धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें, तो वे न केवल अपने आर्थिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। सूरत जैसे शहर में इस तरह का आयोजन यह दर्शाता है कि यहां के निवेशक और उद्योगपति केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को समझने और उसके अनुसार खुद को ढालने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। ‘इन्वेस्टमेंट फोरम 2.0’ ने न केवल निवेशकों को नई दिशा दी, बल्कि यह भी साबित किया कि सही मार्गदर्शन और जागरूकता के साथ कोई भी निवेशक अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है।

मजबूती की राह पर ICICI बैंक: चौथी तिमाही में मुनाफा उछला, पूरे साल के नतीजों ने दिखाई दमदार ग्रोथ की तस्वीर

मुंबई। देश के निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों में शामिल ICICI Bank ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजों के साथ एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के दम पर बैंकिंग सेक्टर में अपनी स्थिति और भी सुदृढ़ कर रहा है। मार्च 2026 तिमाही के आंकड़ों में बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ 9.28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14,755 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 13,502 करोड़ रुपये था। यह वृद्धि न केवल बैंक के ऑपरेशनल प्रदर्शन को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बैंक ने अपने विकास की गति को बरकरार रखा है। बैंक के स्टैंडअलोन प्रदर्शन पर नजर डालें तो यहां भी मजबूती साफ दिखाई देती है। एकल आधार पर शुद्ध लाभ 8.5 प्रतिशत बढ़कर 13,702 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 12,630 करोड़ रुपये था। यह संकेत देता है कि बैंक का कोर बिजनेस यानी लोन बुक, डिपॉजिट बेस और ब्याज आय का ढांचा लगातार मजबूत बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्थिर वृद्धि बैंक की रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन और डिजिटल विस्तार का परिणाम है, जिसने उसे प्रतिस्पर्धा के बीच भी बढ़त बनाए रखने में मदद की है।

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े इस मजबूत प्रदर्शन को और स्पष्ट करते हैं। बैंक का कर-पश्चात लाभ (PAT) 6.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 50,147 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 47,227 करोड़ रुपये था। यह निरंतर वृद्धि दर्शाती है कि बैंक केवल तिमाही आधार पर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्तर पर भी स्थिर और सतत विकास कर रहा है। ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक माहौल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, यह प्रदर्शन निवेशकों और बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

बैंक की आय संरचना पर नजर डालें तो शुद्ध ब्याज आय (NII) में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 22,979 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह आंकड़ा दर्शाता है कि बैंक की मुख्य आय, जो ऋण वितरण और ब्याज दरों के अंतर से आती है, लगातार मजबूत हो रही है। इसके साथ ही गैर-ब्याज आय (ट्रेजरी आय को छोड़कर) भी 5.6 प्रतिशत बढ़कर 7,415 करोड़ रुपये हो गई, जो यह दर्शाती है कि बैंक अपने आय स्रोतों को विविध बनाने में भी सफल रहा है। इस संतुलित वृद्धि ने बैंक को स्थिर लाभप्रदता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हालांकि तिमाही के दौरान बैंक के परिचालन व्यय में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 12,089 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद बैंक ने अपने मुनाफे पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बढ़ता खर्च मुख्य रूप से तकनीकी निवेश, शाखा विस्तार और मानव संसाधन पर किए गए खर्च के कारण है, जो भविष्य की वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार का निवेश बैंक की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे आने वाले समय में और बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी बैंक ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है, जो किसी भी वित्तीय संस्थान की मजबूती का प्रमुख संकेतक होता है। सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.40 प्रतिशत रह गया है, जो दिसंबर तिमाही में 1.53 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 1.67 प्रतिशत था। यह गिरावट दर्शाती है कि बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को बेहतर तरीके से संभाला है और जोखिम प्रबंधन में सुधार किया है। इसके साथ ही प्रावधान (Provisioning) में भी भारी कमी आई है, जो घटकर 96.16 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 891 करोड़ रुपये था। यह बदलाव स्पष्ट रूप से बताता है कि बैंक के सामने संभावित जोखिम कम हुए हैं और उसकी वित्तीय स्थिति अधिक स्थिर हुई है।

इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ICICI बैंक ने न केवल अपनी आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है, बल्कि जोखिम को नियंत्रित रखते हुए लाभप्रदता को भी बनाए रखा है। यह संतुलन ही किसी भी बैंक की असली ताकत होता है, और ICICI बैंक ने इसे बखूबी साबित किया है। बैंक की लोन ग्रोथ, मजबूत डिपॉजिट बेस और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार उसे प्रतिस्पर्धी बाजार में आगे बनाए रखने में मदद कर रहा है।

रेलमार्ग बंद, यात्रियों की राह मुश्किल-चूरू से सादुलपुर तक मेगा ब्लॉक ने थामा सफर का पहिया

उत्तर पश्चिम रेलवे के चूरू–सादुलपुर रेलखंड पर जारी विकास कार्यों ने जहां भविष्य में बेहतर और तेज रेल सेवाओं की उम्मीद जगाई है, वहीं वर्तमान में हजारों यात्रियों के लिए यह अवधि भारी परेशानी का कारण बन गई है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लिए गए मेगा ब्लॉक के चलते इस पूरे सेक्शन पर रेल यातायात लगभग ठप हो गया है। करीब 57.82 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर डबल लाइन बिछाने और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का कार्य चल रहा है, जिसके कारण 14 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, 20 से अधिक ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है और 30 से ज्यादा ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है।

इस अचानक हुए बदलाव ने चूरू, सादुलपुर, झुंझुनूं, सीकर, चिड़ावा और नवलगढ़ जैसे इलाकों के यात्रियों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। खासतौर पर वे लोग जो रोजाना नौकरी, व्यापार या पढ़ाई के लिए इन ट्रेनों पर निर्भर थे, अब उन्हें बसों या निजी साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि इन क्षेत्रों में बस सेवाएं पहले से ही सीमित हैं, जिससे अब बसों में अत्यधिक भीड़ देखने को मिल रही है। कई यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ को खड़े होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है।

रेलवे द्वारा लिए गए इस निर्णय का असर केवल स्थानीय यात्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जयपुर-बठिंडा ट्रेन को 30 अप्रैल तक केवल लोहारू तक सीमित कर दिया गया है, जिससे आगे की यात्रा के लिए यात्रियों को अलग से व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं हनुमानगढ़-जयपुर ट्रेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे इस रूट के यात्रियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रेवाड़ी-सीकर ट्रेन भी सीमित रूप में संचालित हो रही है, जिससे यात्रा की सुविधा और भी कम हो गई है।

गर्मी के इस मौसम में जब यात्रियों की संख्या पहले ही बढ़ जाती है, ऐसे समय में ट्रेनों का रद्द होना लोगों के लिए और भी ज्यादा परेशानी लेकर आया है। कई परिवारों ने पहले से यात्रा की योजना बना रखी थी, लेकिन अब उन्हें या तो अपनी यात्रा टालनी पड़ रही है या फिर महंगे वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे आम लोगों के बजट पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह मेगा ब्लॉक भविष्य की बेहतर सेवाओं के लिए जरूरी है। डबल लाइन बनने से ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी, देरी कम होगी और अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो पाएगा। वहीं ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम से सुरक्षा और दक्षता दोनों में सुधार आएगा। अमित सुदर्शन ने बताया कि इस कार्य के पूरा होने के बाद यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज सेवा मिलेगी, जिससे यात्रा अनुभव बेहतर होगा।

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। अब तक 38 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, जिन्होंने 1000 से अधिक ट्रिप पूरे किए हैं। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या और बढ़ाने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके बावजूद जमीनी हकीकत यही है कि फिलहाल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के लोग, जिनके पास सीमित संसाधन हैं, वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रेलवे का यह विकास कार्य भले ही भविष्य के लिए फायदेमंद हो, लेकिन वर्तमान में यह आम आदमी की यात्रा को कठिन बना रहा है।

ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि रेलवे प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को और मजबूत करे—जैसे अतिरिक्त बस सेवाएं, बेहतर सूचना प्रणाली और यात्रियों के लिए हेल्पडेस्क की व्यवस्था—ताकि इस अस्थायी परेशानी को कुछ हद तक कम किया जा सके। फिलहाल यात्रियों के लिए यही सलाह है कि वे धैर्य रखें और अपनी यात्रा की योजना बनाते समय पूरी जानकारी के साथ ही आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाले दिनों में यह स्थिति तब तक बनी रह सकती है, जब तक यह महत्वपूर्ण रेल परियोजना पूरी नहीं हो जाती।

सस्ते इलाज से ग्लोबल हेल्थ हब तक: बदलती रणनीति के साथ भारत की नई उड़ान

नई दिल्ली। दुनिया के हेल्थकेयर नक्शे पर भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। लंबे समय तक “कम लागत में बेहतर इलाज” के लिए पहचाना जाने वाला भारत अब अपनी छवि को एक कदम आगे ले जाकर खुद को ग्लोबल हेल्थ हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह बदलाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी निवेश, डॉक्टरों की विशेषज्ञता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। अब भारत केवल सस्ता इलाज देने वाला देश नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता, अत्याधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला एक भरोसेमंद केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय स्थान बनाया है। 2019 में जहां लगभग 6.97 लाख विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आए थे, वहीं महामारी और वैश्विक परिस्थितियों के प्रभाव के बावजूद 2025 में जनवरी से नवंबर के बीच करीब 4.5 लाख मरीज भारत पहुंचे। यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के हेल्थकेयर सिस्टम पर भरोसा लगातार बना हुआ है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भू-राजनीतिक तनाव, वीजा प्रक्रियाओं की जटिलता और अंतरराष्ट्रीय यात्रा में आई बाधाओं ने इस वृद्धि को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है।

भारत में मेडिकल टूरिज्म की रीढ़ लंबे समय तक पड़ोसी देशों, खासकर बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले मरीज रहे हैं। लेकिन हाल के समय में राजनीतिक और वीजा से जुड़ी चुनौतियों के कारण इन देशों से आने वाले मरीजों की संख्या में कुछ गिरावट देखी गई है। इसके बावजूद हेल्थकेयर इंडस्ट्री को पूरा विश्वास है कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, मरीजों की संख्या फिर तेजी से बढ़ेगी। यही कारण है कि अब भारत अपनी रणनीति को व्यापक बनाते हुए नए बाजारों की ओर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

वैश्विक स्तर पर मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी तेजी से बढ़ी है। थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश आधुनिक सुविधाओं और बेहतर मरीज अनुभव के दम पर इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बना चुके हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती केवल लागत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की नहीं है, बल्कि गुणवत्ता, तकनीक और सेवा स्तर के आधार पर खुद को बेहतर साबित करने की है। यही वजह है कि अब भारत का फोकस “लो-कॉस्ट” मॉडल से हटकर “हाई-वैल्यू” हेल्थकेयर पर केंद्रित हो गया है।

देश के प्रमुख अस्पताल समूह, जैसे Apollo Hospitals और Max Healthcare, इस बदलाव के केंद्र में हैं। ये संस्थान रोबोटिक सर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायग्नोस्टिक्स, अत्याधुनिक आईसीयू सुविधाएं और तेज एवं सटीक उपचार पर बड़े स्तर पर निवेश कर रहे हैं। जटिल बीमारियों—जैसे कैंसर, हृदय रोग और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर—के इलाज में भारत पहले ही अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। अब इन सेवाओं को और उन्नत बनाकर वैश्विक मरीजों के लिए आकर्षक बनाया जा रहा है।

मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भी कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पताल अब केवल इलाज तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि मरीजों को संपूर्ण देखभाल (end-to-end care) प्रदान करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें भाषा सहायता, अंतरराष्ट्रीय मरीजों के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था, तथा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह सब मिलकर भारत को एक ऐसा हेल्थ डेस्टिनेशन बना रहे हैं, जहां मरीज न केवल इलाज के लिए आते हैं, बल्कि उन्हें संपूर्ण संतुष्टि और भरोसा भी मिलता है।

इसके साथ ही भारत अब अपने मेडिकल टूरिज्म के दायरे को भी बढ़ा रहा है। पारंपरिक बाजारों के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया और CIS देशों जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन देशों के मरीजों के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि उन्हें भारत में इलाज के लिए आकर्षित किया जा सके। यह रणनीति न केवल मरीजों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान को भी मजबूत करेगी।

हालांकि, इस दिशा में कुछ चुनौतियां भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत को वास्तव में ग्लोबल हेल्थ हब बनना है, तो वीजा प्रक्रिया को और अधिक सरल और तेज बनाना होगा। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता बनाए रखना और स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार करना भी आवश्यक होगा। यदि इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, तो भारत के पास मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है।

इस रणनीतिक बदलाव का प्रभाव केवल हेल्थकेयर सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालेगा। विदेशी मरीजों के आने से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और हेल्थकेयर से जुड़े अन्य क्षेत्रों—जैसे फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण और हॉस्पिटैलिटी—को भी लाभ मिलेगा।

कुल मिलाकर, भारत अब मेडिकल टूरिज्म के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां उसकी पहचान केवल सस्ते इलाज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गुणवत्ता, भरोसे और अत्याधुनिक तकनीक के दम पर वह दुनिया के प्रमुख हेल्थकेयर केंद्रों में अपनी जगह मजबूत करेगा।

“हाईटेक जासूसी का जाल: गाजियाबाद से देशभर में फैले नेटवर्क पर NIA की नजर”

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आए एक बेहद संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत जासूसी कांड ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह कोई साधारण आपराधिक मामला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है, जिसके तार सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी Inter-Services Intelligence (ISI) से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। अब इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की कमान National Investigation Agency (NIA) को सौंपे जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीरता से ले रही है।

गाजियाबाद पुलिस द्वारा की गई शुरुआती कार्रवाई में इस नेटवर्क का जो खुलासा हुआ है, उसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। अब तक 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और पूछताछ के दौरान यह सामने आया है कि यह गिरोह केवल एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका विस्तार दिल्ली, मुंबई और अन्य कई राज्यों तक फैला हुआ था। इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली इतनी व्यवस्थित और गुप्त थी कि लंबे समय तक यह सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचा रहा।

जांच में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह सामने आया है कि आरोपियों ने जासूसी के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने संवेदनशील इलाकों, खासकर आर्मी कैंट और रणनीतिक ठिकानों के आसपास सोलर पावर्ड CCTV कैमरे लगाए थे। ये कैमरे सामान्य निगरानी उपकरणों की तरह दिखते थे, जिससे किसी को भी उन पर शक नहीं होता था। लेकिन इन कैमरों के जरिए जो डेटा और लाइव फुटेज एकत्र किया जा रहा था, वह सीधे पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर्स तक पहुंचाया जा रहा था। सोलर सिस्टम के इस्तेमाल के कारण ये कैमरे बिना बिजली कनेक्शन के लंबे समय तक सक्रिय रह सकते थे, जिससे इनकी पहचान करना और भी कठिन हो गया।

यह पूरा मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि इसमें सेना के ठिकानों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को निशाना बनाया गया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल जासूसी के दायरे में आती हैं, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा भी हैं। सैन्य गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग किसी भी देश के लिए अत्यंत संवेदनशील जानकारी होती है, और यदि यह दुश्मन देश तक पहुंचती है, तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, National Investigation Agency ने इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और केस डायरी अपने कब्जे में ले ली है। एजेंसी जल्द ही इस केस में औपचारिक रूप से प्रवेश कर सकती है, जिसके बाद जांच का दायरा और भी व्यापक हो जाएगा। NIA इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, फंडिंग के स्रोत और देशभर में फैले इसके नेटवर्क की गहराई से जांच करेगी।

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से दोबारा पूछताछ की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं या नहीं। जांच एजेंसियां इस संभावना से इनकार नहीं कर रही हैं कि यह नेटवर्क और भी बड़े स्तर पर काम कर रहा हो सकता है, जिसके कई हिस्से अभी सामने आना बाकी हैं।

इस घटना के बाद देशभर की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही, तकनीकी उपकरणों और सर्विलांस सिस्टम की भी जांच की जा रही है, ताकि इस तरह के किसी भी खतरे को समय रहते रोका जा सके।

यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर यह दर्शाता है कि आधुनिक दौर में जासूसी के तरीके कितने बदल चुके हैं। अब जासूसी केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल नेटवर्क और रिमोट मॉनिटरिंग जैसे साधनों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती भी उतनी ही बड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें न केवल पारंपरिक खतरों से निपटना है, बल्कि तकनीकी रूप से उन्नत नेटवर्क का भी मुकाबला करना है।

गाजियाबाद से शुरू हुआ यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है, और आने वाले दिनों में इसकी जांच से कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल, देश की सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने और इसके पीछे छिपे हर कड़ी को उजागर करने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई हैं।